नरेश कुमार यादव

बनाम

रवीन्द्र कुमार और अन्य।

अक्टूबर 23, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं श्री लोकेश्वर सिंह पंता, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 438- संरक्षण के तहत – अभिनिर्धारित किया गया: सीमित अवधि के लिए है जिसके दौरान नियमित न्यायालय में ज़मानत के लिए जाना होता है – आवेदक को यह दिखाना होगा कि उसके पास यह 'विश्वास करने का कारण' है कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है – विश्वास केवल तर्कसंगत आधारों पर ही स्थापित होना चाहिए यदि यह दिखाने के लिए कुछ ठोस है कि उसकी यह आशंका कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, वास्तविक है – आवेदक को जमानत पर रिहा करने का निर्देश "चाहे किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया हो" नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हर तरह की कथित गैरकानूनी गतिविधियों को संरक्षण मिल जाएगा। – तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने गलत ढंग से यह टिप्पणी की कि अभियुक्त व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी में नहीं था और उन्हें धारा 43 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया था। – अतः, उच्च न्यायालय का आदेश संधारणीय नहीं है – ज़मानत – अग्रिम ज़मानत।

धारा 438 और 439 – के बीच अंतर – चर्चा की गई।

धारा 207 और 208 – का उद्देश्य – अभिनिर्धारित किया गया: अभियुक्त को ठीक से अपना बचाव करने में सक्षम बनाना।

वाद-दैनिकी – सूचक और अभियुक्त, ज़मानत आवेदन की सुनवाई पर अपने रुख के समर्थन में वाद-दैनिकी के अंशों का संदर्भ देते हुए – अभिनिर्धारित किया गया: कानूनी रूप

से उन्हें इन सरकारी अभिलेखों तक पहुंच नहीं होनी चाहिए – अतः न्यायालयों को इसका गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए।

शब्द और वाक्यांश:

'विश्वास करने का कारण' – का अर्थ – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संदर्भ में।

वर्तमान अपील सूचक द्वारा दायर की गई है, जो उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें उत्तरदाता सं. 1, 2 और 3 को धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संरक्षण की मांग करने की प्रार्थना को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया था कि ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय ने ऐसे संरक्षण को देने के मापदंड को ध्यान में नहीं रखा; कि उच्च न्यायालय ने आरोपों को तय करने से पहले ही निर्णय ले लिया था और गलत तरीके से यह भी नोट किया कि अभियुक्तों के नाम प्राथमिकी में नहीं थे।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से यह भी अभिलिखित किया कि अभियुक्तों के नाम प्राथमिकी में नहीं थे; वास्तव में उनका नाम स्पष्ट रूप से लिया गया था। [कंडिका 5][620-ई]

1.2 वह सुविधा जो धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदान करती है, उसे सामान्यतः 'अग्रिम ज़मानत' के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह अभिव्यक्ति जो विधि आयोग ने अपनी 41वीं प्रतिवेदन में उपयोग की थी, न तो इस धारा में और न ही इसके सीमांत नोट में उपयोग की जाती है। लेकिन 'अग्रिम ज़मानत' की अभिव्यक्ति यह इंगित करने का एक सुविधाजनक माध्यम है कि गिरफ्तारी की आशंका में ज़मानत के लिए आवेदन करना संभव है। ज़मानत का कोई भी आदेश अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय से ही प्रभावी हो सकता है। 'ज़मानत' मूल रूप से नियंत्रण से रिहाई है, विशेष रूप से पुलिस की अभिरक्षा से। एक साधारण ज़मानत आदेश और धारा 438 के तहत एक आदेश के बीच का अंतर यह है कि जहाँ पहला गिरफ्तारी के बाद दिया जाता है, और इसलिए पुलिस की अभिरक्षा से रिहाई का

मतलब है, वहीं बाद वाला गिरफ्तारी की आशंका में दिया जाता है और इसलिए गिरफ्तारी के ठीक उसी क्षण प्रभावी होता है। [कंडिका 6][620-एफ, जी, एच; 621-ए]

गुर बख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1980] 2 एस सी सी 565, पर अवलंबन किया गया।

व्हार्टन की विधि शब्दकोश, संदर्भित है।

2.1 धारा 438 के तहत प्रयोज्य शक्ति कुछ हद तक असाधारण प्रकृति की है और यह केवल अपवादात्मक मामलों में ही है जहाँ ऐसा लगता है कि व्यक्ति को झूठा फंसाया जा सकता है या जहाँ यह मानने के लिए तर्कसंगत आधार हैं कि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, तभी धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। शक्ति महत्वपूर्ण प्रकृति की होने के कारण, इसे केवल न्यायिक मंचों के उच्चतर स्तरों, अर्थात् सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को सौंपा गया है। यह गैर-जमानती अपराध के पूर्वानुमानित आरोप के मामले में प्रयोज्य शक्ति है। धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा जो उद्देश्य हासिल करने की कोशिश की जाती है, वह यह है कि जिस क्षण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यदि उसने पहले ही सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त कर लिया है, तो उसे जेल भेजे बिना तुरंत ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

[कंडिका 6][621-डी, ई, एफ]

बालचंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. (1977) एस सी 366, संदर्भित है।

2.2 धारा 438 के संदर्भ में संरक्षण एक सीमित अवधि के लिए है जिसके दौरान नियमित न्यायालय को ज़मानत के लिए जाना होता है। जाहिर है, ऐसी ज़मानत धारा 439 के संदर्भ में ज़मानत है, जिसके लिए आवेदक को अभिरक्षा में होना अनिवार्य है। अन्यथा, धारा 438 और 439 के तहत आदेशों के बीच का अंतर अर्थहीन और अनावश्यक हो जाएगा।

[कंडिका 13][624-डी]

सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, **ए.आई.आर. (1996) एस सी 1042, पर अवलंबन किया गया।**

के.एल. वर्मा बनाम राज्य और एक अन्य। **(1996) 7 एस.सी.ए.एल.ई. 20;** *निर्मल जीत कौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य।,* **[2004] 7 एस सी सी 558**; सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य और *एक* अन्य।, **[आपराधिक अपील जो एस.एल.पी. (आपराधिक) सं. 4601 वर्ष 2003 से उत्पन्न हुई, जिसका निपटारा 6.12.2004 को किया गया]** और *निरंजन सिंह और एक अन्य। बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे और अन्य।,* **ए.आई.आर. (1980) एस सी 785, संदर्भित है।**

3. धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है जिसे निर्दोषता का दावा करने का अधिकार है, चूंकि धारा 438 के तहत शक्ति के प्रयोग हेतु आवेदन की तिथि पर वह उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसके लिए वह जमानत मांग रहा है। आवेदक को यह दिखाना होगा कि उसके पास यह 'विश्वास करने का कारण' है कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति 'विश्वास करने का कारण' कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, का उपयोग यह दिखाता है कि आवेदक की गिरफ्तारी तर्कसंगत आधारों पर स्थापित होनी चाहिए। महज "डर" 'विश्वास' नहीं है, जिसके कारण आवेदक के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि उसे कुछ अस्पष्ट आशंका है कि कोई उसके खिलाफ एक आरोप लगाने जा रहा है जिसके तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिन आधारों पर आवेदक का यह विश्वास आधारित है कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी जांच होने में सक्षम होना चाहिए।

[कंडिका 15][624-एफ, जी; 625-ए]

4. यदि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय को यह तय करना होता है कि मांगी गई राहत देने के लिए कोई मामला

बना है या नहीं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। एक सामान्य आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। यह धारा की वास्तविक भाषा से उत्पन्न होता है जिसमें आवेदक को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एक विश्वास को तर्कसंगत आधारों पर स्थापित केवल तभी कहा जा सकता है जब कुछ ठोस हो जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आवेदक की यह आशंका कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, वास्तविक है। सामान्यतः यह निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए कि आवेदक को "जब भी किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाए" तो ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इस प्रकार का 'सामान्य आदेश' पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कथित तौर पर हर प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि को छिपाने या संरक्षित करने के लिए एक आवरण के रूप में कार्य करेगा। धारा 438 के तहत एक आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का एक साधन है, यह न तो अपराधों को करने का पासपोर्ट है और न ही किसी भी और हर प्रकार के संभावित या असंभावित आरोपों के विरुद्ध ढाल। मामले के तथ्यों पर, ऊपर निर्धारित कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में विचार करते हुए, यह प्रथम दृष्ट्या ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है जहाँ धारा 438 के संदर्भ में कोई आदेश पारित किया जा सके। [कंडिका 15][625-बी, सी, डी, ई]

अद्रि धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, [2005] 4 एस.सी.सी 303, पर अवलंबन किया गया।

5.1 कानून के सिद्धांतों और शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य के मद्देनज़र, उत्तरदाता को संबंधित न्यायालय के समक्ष चार सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने और नियमित ज़मानत चाहने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त नहीं की जाती है। अभियुक्त और सूचक दोनों ने वाद-दैनिकी के कई अंशों का संदर्भ दिया। अभियुक्त को उन सामग्रियों से अवगत कराने के लिए जो उसके विरुद्ध उपयोग करने

की कोशिश की जा रही हैं, धारा 207 और 208 के संदर्भ में दस्तावेज दिए जाते हैं। उद्देश्य अभियुक्त को ठीक से अपना बचाव करने में सक्षम बनाना है। प्रतियों की आपूर्ति के पीछे का विचार उसे इस बात का सूचना देना है कि उसे विचारण में क्या मुकाबला करना है।

[कंडिका 17, 18, 21 और 23][625-एफ, जी; 626-ई; 628-बी, सी]

नूर खान बनाम राजस्थान राज्य, **ए.आई.आर. (1964) एस.सी 286 और** *शकीला अब्दुल गफ़र खान (श्रीमती) बनाम वसंत रघुनाथ धोब्ले और एक अन्य।,* **[2003] 7 एस.सी.सी 749, पर अवलंबन किया गया।**

5.2 यह जानकर हैरानी होती है कि अभियुक्त और सूचक ने वाद-दैनिकी के विशेष अंशों का संदर्भ दिया। जिस चरण पर उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत आवेदन सुने गए थे, कानूनी रूप से वे उन तक पहुंच बनाने की स्थिति में नहीं हो सकते थे। जो कागजात अभियुक्त को दिए जाने हैं, वे सांविधिक रूप से निर्धारित किए गए हैं। न्यायालयों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए जब अभियुक्त या सूचक एक रुख को समर्थन देने के लिए वाद-दैनिकी का संदर्भ देते हैं। [कंडिका 24][628-एफ, जी]

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: 2007 की आपराधिक अपील सं. 1462।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2005 की आपराधिक विविध वाद संख्या 34337 के साथ आपराधिक विविध वाद संख्या 35682 और 34139 वर्ष 2005 में दिनांक 10.7.2006 के निर्णय और अंतिम आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए: सुनील कुमार, राजीव शंकर द्विवेदी और अजय चौधरी।

उत्तरदाताओं के लिए: पी.एस. मिश्रा और रणजीत कुमार, अमित पवन, गोपाल सिंह और मनीष कुमार।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अरिजीत पसायत, 1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में चुनौती सूचक द्वारा पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश

(ए.न्या.) द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें उत्तरदाता सं. 1, 2 और 3 द्वारा दायर तीन याचिकाओं का निपटारा किया गया था। उक्त याचिकाओं द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 438 के संदर्भ में संरक्षण की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी।

3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 438 के संदर्भ में संरक्षण की अनुमति देते समय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा ऐसे संरक्षण देने के लिए इंगित मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा। यहां तक कि अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने आरोपों के गठन को रोक दिया है। यह भी बताया गया है कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर कई त्रुटियां कीं, उदाहरण के लिए उसने टिप्पणी की कि अभियुक्त व्यक्तियों का नाम प्रथम सूचना प्रतिवेदन (संक्षेप में 'प्राथमिकी') में नहीं था हालांकि उनका नाम प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से लिया गया था।

4. दूसरी ओर उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक को खत्म करने के किसी भी षड्यंत्र में अभियुक्त व्यक्तियों के शामिल होने को दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के बिना, *दुर्भावनापूर्ण* इरादे से झूठे आरोप लगाए गए हैं। मृतक कई मामलों में शामिल था। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने इस स्थिति का संज्ञान लिया था कि कथित षड्यंत्र के लिए उत्तरदाताओं से संबंधित सामग्रियां वाद-दैनिकी की कंडिका 39, 41 और 42 में शामिल थीं। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सूचक के अधिवक्ता ने भी यह स्वीकार किया था कि उनमें अभियुक्त व्यक्तियों से संबंधित सामग्रियां शामिल थीं।

5. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया है, संहिता की धारा 438 के तहत व्यापक संरक्षण प्रदान करना परिकल्पित नहीं है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण में यह भी सार है कि उच्च न्यायालय ने गलती से टिप्पणी की कि अभियुक्त व्यक्तियों का नाम प्राथमिकी में नहीं था, वास्तव में उनका नाम स्पष्ट रूप से लिया गया था।

6. वह सुविधा जो संहिता की धारा 438 प्रदान करती है, उसे सामान्यतः 'अग्रिम ज़मानत' के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह अभिव्यक्ति जो विधि आयोग ने अपनी 41वीं

प्रतिवेदन में उपयोग की थी, न तो इस धारा में और न ही इसके सीमांत नोट में उपयोग की जाती है। लेकिन 'अग्रिम ज़मानत' की अभिव्यक्ति यह इंगित करने का एक सुविधाजनक माध्यम है कि गिरफ्तारी की आशंका में ज़मानत के लिए आवेदन करना संभव है। ज़मानत का कोई भी आदेश अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय से ही प्रभावी हो सकता है। व्हार्टन की विधि शब्दकोश 'ज़मानत' को 'एक गिरफ्तार या कैद किए गए व्यक्ति को उसकी उपस्थिति के लिए सुरक्षा लेने पर स्वतंत्र करना' के रूप में समझाती है। इस प्रकार ज़मानत मूल रूप से नियंत्रण से रिहाई है, विशेष रूप से पुलिस की अभिरक्षा से। एक साधारण ज़मानत आदेश और संहिता की धारा 438 के तहत एक आदेश के बीच का अंतर यह है कि जहाँ पहला गिरफ्तारी के बाद दिया जाता है, और इसलिए पुलिस की अभिरक्षा से रिहाई का मतलब है, वहीं बाद वाला गिरफ्तारी की आशंका में दिया जाता है और इसलिए गिरफ्तारी के ठीक उसी क्षण प्रभावी होता है। (देखें: *गुर बख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य,* [1980] 2 एस.सी.सी 565)। संहिता की धारा 46(1), जो गिरफ्तारी करने के तरीके से संबंधित है, यह प्रावधान करती है कि गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, "गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तव में स्पर्श या कैद नहीं करेगा, जब तक कि वह व्यक्ति शब्दों या कार्यों द्वारा हिरासत में आत्मसमर्पण न कर दे"। संहिता की धारा 438 के तहत आदेश धारा 46 (1) द्वारा परिकल्पित स्पर्श या किसी भी परिरोध से सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करने का इरादा रखता है। इस न्यायालय ने *बालचंद जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर.* (1977) एस.सी 366 में 'अग्रिम ज़मानत' की अभिव्यक्ति को भ्रामक बताया है। यह सर्वविदित है कि ज़मानत गिरफ्तारी की साधारण अभिव्यक्ति है, कि न्यायालय पहले जो आदेश देना चाहता है वह यह है कि गिरफ्तारी की स्थिति में एक व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। स्पष्ट रूप से ज़मानत पर रिहा करने का कोई प्रश्न नहीं है जब तक कि अभियुक्त को गिरफ्तार न किया जाए, और इसलिए, यह आदेश केवल गिरफ्तारी के प्रभावित होने पर ही प्रभावी होता है। धारा 438 के तहत प्रयोज्य शक्ति कुछ

हद तक असाधारण प्रकृति की है और यह केवल अपवादात्मक मामलों में ही है जहाँ ऐसा लगता है कि व्यक्ति को झूठा फंसाया जा सकता है या जहाँ यह मानने के लिए तर्कसंगत आधार हैं कि अपराध का अभियुक्त व्यक्ति अन्यथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, तभी धारा 438 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। शक्ति महत्वपूर्ण प्रकृति की होने के कारण, इसे केवल न्यायिक मंचों के उच्चतर स्तरों, अर्थात् सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को सौंपा गया है। यह गैर-जमानती अपराध के पूर्वानुमानित आरोप के मामले में प्रयोज्य शक्ति है। संहिता की धारा 438 द्वारा जो उद्देश्य हासिल करने की कोशिश की जाती है, वह यह है कि जिस क्षण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यदि उसने पहले ही सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त कर लिया है, तो उसे जेल भेजे बिना तुरंत ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

7. धारा 438 और 439 अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होती हैं। संहिता की धारा 439 इस प्रकार है:

> "439. (1) एक उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है:
>
> (क) कि अपराध का कोई भी अभियुक्त व्यक्ति जो *अभिरक्षा में है, ज़मानत पर रिहा किया जाए,* और यदि अपराध धारा 437 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो कोई भी शर्त लगा सकता है जो वह उस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझता है;
>
> (ख) कि किसी व्यक्ति को ज़मानत पर रिहा करते समय दंडाधिकारी द्वारा लगाई गई कोई भी शर्त अपास्त या संशोधित की जाए।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकित)

8. प्रावधानों के एक सरल पठन से यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 439 के संदर्भ में आवेदन करने के लिए एक व्यक्ति को अभिरक्षा में होना चाहिए। संहिता की धारा 438 "गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को ज़मानत देने का निर्देश" से संबंधित है।

9. *सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य,* ए.आई.आर. (1996) एस.सी 1042 में यह अवलोकित किया गया था:

"गैर-जमानती मामलों में गिरफ्तारी की आशंका में अग्रिम ज़मानत दी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नियमित न्यायालय, जिसे अपराधी पर मुकदमा चलाना है, को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है और यही कारण है कि उच्च न्यायालय ने ज़मानत जारी रखने की बाहरी तारीख़ तय करके और उसकी समाप्ति की तारीख़ पर याचिकाकर्ता को ज़मानत के लिए नियमित न्यायालय में जाने का निर्देश देकर बिल्कुल सही किया। यही सही प्रक्रिया है क्योंकि यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय अग्रिम ज़मानत देता है, तो यह उस समय दी जाती है जब जाँच पूरी नहीं होती और इसलिए उसे कथित अपराधी के ख़िलाफ़ सबूतों की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं होती। *इसलिए, यह आवश्यक है कि ऐसे अग्रिम ज़मानत आदेश केवल सीमित अवधि के हों और सामान्यतः उस अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर अग्रिम ज़मानत देने वाली न्यायालय को यह काम नियमित न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए* कि वह जाँच में प्रगति होने या आरोप-पत्र प्रस्तुत होने के बाद उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले का निपटारा करे।"

(जोर दिया गया)

10. *के.एल. वर्मा बनाम राज्य और एक अन्य।*, (1996) 7 एस.सी.ए.एल.ई 20 में इस न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया:

"इस न्यायालय ने आगे अवलोकन किया कि अग्रिम ज़मानत गैर-जमानती मामलों में गिरफ्तारी की आशंका में दी जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नियमित न्यायालय, जो अपराधी पर विचारण करने वाला है, को

दरकिनार करने की कोशिश की जाती है। इसलिए, यह बताया गया कि यह आवश्यक था कि ऐसे अग्रिम ज़मानत आदेश केवल सीमित अवधि के हों और सामान्यतः उस अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर अग्रिम ज़मानत देने वाला न्यायालय को नियमित न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए कि वह अनुसंधान की प्रगति या आरोप पत्र जमा होने के बाद उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य के मूल्यांकन पर मामले का निपटारा करे। इससे, न्यायालय ने जो संदेश देना चाहा वह यह था कि अग्रिम ज़मानत का एक आदेश विचारण के अंत तक जारी नहीं रहता है बल्कि इसकी अवधि सीमित होनी चाहिए क्योंकि नियमित न्यायालय को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सीमित अवधि का निर्धारण मामले के तथ्यों और अभियुक्त को नियमित न्यायालय में ज़मानत के लिए जाने के लिए पर्याप्त समय देने और नियमित न्यायालय को ज़मानत आवेदन का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त समय देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब तक ज़मानत आवेदन का निपटारा एक या दूसरे तरीके से नहीं हो जाता, न्यायालय अभियुक्त को अग्रिम ज़मानत पर रहने की अनुमति दे सकता है। *इसे अलग तरह से कहें, तो अग्रिम ज़मानत एक ऐसी अवधि के लिए दी जा सकती है जो उस तारीख तक विस्तारित हो सकती है जिस पर ज़मानत आवेदन का निपटारा किया जाता है या यहाँ तक कि उसके कुछ दिन बाद तक भी ताकि अभियुक्त व्यक्तियों को उच्चतर न्यायालय में जाने में सक्षम बनाया जा सके, यदि वे ऐसा चाहते हैं।"*

(जोर दिया गया)

11. *निर्मल जीत कौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य।,* [2004] *7* एस.सी .सी 558 और *सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य और एक अन्य*, आपराधिक अपील जो 2003

की एस.एल.पी. (आपराधिक) सं. 4601 से उत्पन्न हुई, जिसका निपटारा 6.12.2004 को किया गया, में *के.एल. वर्मा के मामले* (उपरोक्त) में कुछ धुंधले क्षेत्रों को देखा गया। यह अवलोकन से संबंधित था "या यहां तक कि उसके कुछ दिन बाद तक भी ताकि अभियुक्त व्यक्तियों को उच्चतर न्यायालय में जाने में सक्षम बनाया जा सके, यदि वे ऐसा चाहते हैं"। यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 439 की आवश्यकता को उपरोक्त अवलोकनों द्वारा मिटाया नहीं जाता। धारा 439 केवल तभी संचालित होती है जब कोई व्यक्ति "अभिरक्षा में" हो। *के.एल. वर्मा* के मामले (उपरोक्त) में *सलाउद्दीन के* मामले (उपरोक्त) का संदर्भ दिया गया था। उक्त मामले में *के.एल. वर्मा* के मामले (उपरोक्त) में दिए गए जैसा कोई संकेत नहीं था, कि अभियुक्त को उच्चतर न्यायालय में जाने के लिए कुछ दिन दिए जा सकते हैं यदि वे ऐसा चाहते हैं। संहिता की धारा 439 की सांविधिक आवश्यकता को उक्त अवलोकन द्वारा पूरी तरह से निष्प्रभावी नहीं कहा जा सकता है।

12. धारा 439 की स्पष्ट भाषा के मद्देनज़र और *निरंजन सिंह और एक अन्य बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे और एक अन्य,* ए.आई.आर. (1980) एस सी 785 में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि जब तक कोई व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं होता, संहिता की धारा 439 के तहत ज़मानत के लिए आवेदन संधार्य नहीं होगा। यह प्रश्न कि किसी व्यक्ति को संहिता की धारा 439 के अर्थ के भीतर अभिरक्षा में कब कहा जा सकता है, उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए आया था।

13. जब कोई व्यक्ति संहिता की धारा 439 के अर्थ के भीतर अभिरक्षा में होता है, तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का विश्लेषण करने के बाद, *निर्मल जीत कौर के* मामले (उपरोक्त) और *सुनीता देवी के* मामले (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 439 के तहत आवेदन करने के लिए मूलभूत आवश्यकता यह है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में होना चाहिए। जैसा कि *सलाउद्दीन के* मामले (उपरोक्त) में अवलोकित किया गया, धारा 438 के संदर्भ में संरक्षण एक सीमित अवधि के लिए है जिसके दौरान नियमित न्यायालय को ज़मानत के

लिए जाना होता है। जाहिर है, ऐसी ज़मानत संहिता की धारा 439 के संदर्भ में ज़मानत है, जिसके लिए आवेदक को अभिरक्षा में होना अनिवार्य है। अन्यथा, धारा 438 और 439 के तहत आदेशों के बीच का अंतर अर्थहीन और अनावश्यक हो जाएगा।

14. यदि धारा 438 का सुरक्षात्मक छाता *सलाउद्दीन के* मामले (उपरोक्त) में निर्धारित से आगे बढ़ाया जाता है, तो परिणाम धारा 439 के अभिरक्षा के संबंध में अनिवार्य को स्पष्ट रूप से दरकिनार करना होगा। दूसरे शब्दों में, जब तक आवेदक उच्चतर न्यायालयों तक उपचार प्राप्त नहीं कर लेता, धारा 439 की आवश्यकताएं मृत पत्र बन जाती हैं। किसी भी क़ानून का कोई भी हिस्सा उस तरीके से अनावश्यक नहीं बनाया जा सकता।

15. धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है जो निर्दोषिता की वकालत करने का हकदार है, चूंकि उसे उस अपराध के संबंध में जिसके लिए वह ज़मानत चाहता है, संहिता की धारा 438 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए आवेदन की तारीख को दोषी नहीं ठहराया गया है। आवेदक को यह दिखाना होगा कि उसके पास यह 'विश्वास करने का कारण' है कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। यह अभिव्यक्ति 'विश्वास करने का कारण' कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, का उपयोग यह दिखाता है कि आवेदक की गिरफ्तारी तर्कसंगत आधारों पर स्थापित होनी चाहिए। महज "डर" 'विश्वास' नहीं है, जिसके कारण आवेदक के लिए यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि उसे कुछ अस्पष्ट आशंका है कि कोई उसके खिलाफ एक आरोप लगाने जा रहा है जिसके तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस आधार पर आवेदक का यह विश्वास आधारित है कि उसे गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, उनका परीक्षण किया जाना सक्षम होना चाहिए। यदि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में कोई आवेदन किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय को यह तय करना होता है कि मांगी गई राहत देने के लिए कोई मामला बना है या नहीं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है। एक सर्वव्यापी आदेश

सामान्यतः पारित नहीं किया जाना चाहिए। यह धारा की वास्तविक भाषा से उत्पन्न होता है जिसमें आवेदक को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी विश्वास को उचित आधारों पर आधारित तभी कहा जा सकता है जब कोई ठोस आधार हो जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आवेदक की यह आशंका कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, वास्तविक है। सामान्यतः यह निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए कि आवेदक को "जब भी किसी भी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाए" तो ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इस तरह का 'व्यापक आदेश' पारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कथित तौर पर हर तरह की गैरकानूनी गतिविधि को ढकने या संरक्षित करने के लिए एक आवरण के रूप में काम करेगा। धारा 438 के तहत एक आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का एक साधन है, यह न तो अपराधों को करने का पासपोर्ट है और न ही किसी भी और हर प्रकार के संभावित या असंभावित आरोपों के विरुद्ध ढाल। मामले के तथ्यों पर, ऊपर निर्धारित कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में विचार करते हुए, यह प्रथम दृष्ट्या ऐसा मामला प्रतीत नहीं होता है जहाँ संहिता की धारा 438 के संदर्भ में कोई आदेश पारित किया जा सके।

16. इन पहलुओं को *अद्रि धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*, [2005] 4 एस.सी .सी 303 में उल्लेखित किया गया है।

17. उपरोक्त वर्णित विधि के सिद्धांतों और संबंधित तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें और नियमित जमानत की मांग करें।

18. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के गुणों पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। जब संहिता की धारा 439 के संदर्भ में ज़मानत आवेदन संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, तो उसी पर कानून के अनुसार उसके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा। यदि ज़मानत के लिए कोई आवेदन पेश किया जाता है, तो संबंधित न्यायालय को इसे उसी

दिन निपटाना चाहिए जिस दिन यह दायर किया जाता है। राज्य की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने यह वचन दिया है कि सभी प्रासंगिक अभिलेख ज़मानत आवेदन से निपटने वाले न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे और यदि अभियुक्त-उत्तरदाता आत्मसमर्पण करने के अपने इरादे की तारीख से तीन दिन पहले सूचित करते हैं, तो अभिलेखों की अनुपलब्धता के आधार पर स्थगन नहीं मांगा जाएगा।

19. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय के निम्नलिखित अवलोकनों पर आरोपों के गठन को रोकने की अपीलकर्ता की आशंका आधारित है:

> "यदि अनुसंधान के पूरा होने पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध वर्तमान में संज्ञान में ली गई सामगुर के अलावा अन्य सामगुर पर आरोप पत्र जमा किया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं के पास कानून के अनुसार अपने उपचार होंगे। "

20. जहाँ तक आरोप पत्र दायर करने और आरोप के गठन का संबंध है, यह कहना अनावश्यक है कि आरोप पत्र अनुसंधान के दौरान संग्रहित सामग्रियों के आधार पर जमा किया जाएगा और दायर किए गए आरोप पत्र पर विचार करते समय संबंधित न्यायालय प्रासंगिक कारकों का संज्ञान लेगा और तय करेगा कि क्या अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप का गठन आवश्यक है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है।

21. इससे पहले कि हम मामले से अलग हों, हम यह इंगित करना आवश्यक महसूस करते हैं कि अभियुक्त और सूचक दोनों ने वाद-दैनिकी के कई अंशों का संदर्भ दिया।

22. संहिता की धारा 207 और 208 उन दस्तावेजों से संबंधित हैं जिन्हें सामान्यतः पुलिस कागजात के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अभियुक्त को दिया जाना है। उक्त धाराएं इस प्रकार हैं:

> *"धारा 207- अभियुक्त को पुलिस प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति:*
>
> किसी भी मामले में जहाँ कार्यवाही एक पुलिस प्रतिवेदन पर संस्थित की गई है, वहां

दंडाधिकारी बिना किसी विलंब के अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा:

(i) पुलिस प्रतिवेदन;

(ii) धारा 154 के तहत दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी);

(iii) उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 की उपधारा (3) के तहत दर्ज कथन जिनका परिक्षण अभियोजन अपने साक्षी के रूप में कराना चाहता है, उसमें से किसी भी ऐसे भाग को छोड़कर जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (6) के तहत ऐसे अपवर्जन के लिए अनुरोध किया गया है;

(iv) धारा 164 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और कथन, यदि कोई हो तो;

(v) कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक अंश जो धारा 173 की उपधारा (5) के तहत पुलिस प्रतिवेदन के साथ दंडाधिकारी को अग्रेषित किया गया है:

परंतु यह कि दंडाधिकारी, किसी कथन के ऐसे भाग का जो खंड (iii) में संदर्भित है और अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके ऐसे अंश की प्रति जो दंडाधिकारी उचित समझता है, अभियुक्त को दी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि दंडाधिकारी संतुष्ट है कि खंड (v) में संदर्भित कोई दस्तावेज विशाल है, तो वह, अभियुक्त को उसकी एक प्रति देने के बजाय, यह निर्देश देगा कि उसे केवल न्यायालय में स्वयं या परामर्शदाता के माध्यम से उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।

धारा 208- सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतियों की आपूर्ति: जहां, किसी मामले में जो पुलिस प्रतिवेदन के अलावा अन्यथा संस्थित किया गया है, धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने वाले

दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो दंडाधिकारी बिना किसी विलंब के अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा:

(i) दंडाधिकारी द्वारा परीक्षित सभी व्यक्तियों के धारा 200 या धारा 202 के तहत दर्ज कथन;

(ii) धारा 161 या धारा 164 के तहत दर्ज कथन और इकबालिया बयान, यदि कोई हो तो;

(iii) दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए कोई भी दस्तावेज जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करने का प्रस्ताव करता है;

परंतु यह कि यदि दंडाधिकारी संतुष्ट है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज विशाल है, तो वह, अभियुक्त को उसकी एक प्रति देने के बजाय, यह निर्देश देगा कि उसे केवल न्यायालय में स्वयं या परामर्शदाता के माध्यम से उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। "

23. धारा 207 और 208 के तहत दस्तावेज उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि अभियुक्त को उन सामग्रियों के बारे में जानकारी हो सके जिनका उपयोग उसके खिलाफ किया जाना है। इसका उद्देश्य अभियुक्त को अपना बचाव ठीक से करने में सक्षम बनाना है। प्रतियों की आपूर्ति के पीछे का विचार उसे इस बात का सूचना देना है कि उसे विचारण में क्या मुकाबला करना है। प्रतियों की गैर-आपूर्ति के प्रभाव पर इस न्यायालय ने *नूर खान बनाम राजस्थान राज्य,* ए.आई.आर. (1964) एस सी 286 और *शकीला अब्दुल गफ़र खान (श्रीमती) बनाम वसंत रघुनाथ धोब्ले और एक अन्य,* [2003] 7 एस.सी.सी 749 में विचार किया है। यह अभिनिर्धारित किया गया थी कि गैर-आपूर्ति आवश्यक रूप से अभियुक्त के लिए हानिकारक नहीं है। न्यायालय को नुकसान या अन्यथा के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष देना होता है। यहां तक कि पर्यवेक्षण टिप्पणियों को भी अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध

सामगुर या साक्ष्य के एक टुकड़े के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि किसी न्यायालय के समक्ष पर्यवेक्षण टिप्पणियों का कोई संदर्भ दिया जाता है, जैसा कि ऊपर अभिलिखित किया गया है, तो संबंधित न्यायालय को उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। चूंकि कई उदाहरण सामने आए हैं जब पक्षों, जैसा कि वर्तमान मामले में है, पर्यवेक्षण टिप्पणियों का संदर्भ देते हैं, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उनके पास सरकारी अभिलेखों तक अनधिकृत पहुंच है।

24. इसके अलावा, यह बात हैरान करने वाली है कि अभियुक्त और सूचक ने वाद-दैनिकी के कुछ खास हिस्सों का हवाला दिया। जिस समय उच्च न्यायालय में जमानत आवेदनों की सुनवाई हुई, उस समय कानूनी तौर पर उन्हें वाद दैनिकी तक पहुंच प्राप्त नहीं हो सकती थी। अभियुक्त को जो कागजात उपलब्ध कराए जाने हैं, वे कानून द्वारा निर्धारित हैं। जब अभियुक्त या सूचक अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए वाद-दैनिकी का हवाला देते हैं, तो न्यायालयों को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

25. अपील का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

डी.जी. अपील का निपटारा किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।